M.Ed - IV Sem
S.C - 4

सामाजिक मांग तथा इसको सन्तुष्ट करने के लिए शैक्षिक तन्त्र की क्षमता के बीच सम्बद्धी शैक्षिक नियोजन का मुख्य बिन्दु है। शिक्षा के लिए इच्छा तथा शैक्षिक प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी के बीच की खाई अनेक प्रकार की आर्थिक-सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। ऐसी अनेक युक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग शैक्षिक तन्त्र मांग और पूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए कर सकता है।

यह अधिक प्रवेश, भीड़ युक्त शिक्षाओं को जन्म दे सकता है तथा सम्भावतया गुणवत्ता में गिरावट ला सकता है। यह युक्ति सामाजिक माँग को सन्तुष्ट कर सकती है लेकिन इसका परिणाम विद्यालय छोड़ने वालों की उच्च दर, स्तर में गिरावट तथा जनसंसाधन का अपव्यय हो सकता है। भारत इस समस्या का सामना लम्बे समय से कर रहा है। शैक्षिक नियोजन का यह मॉडल इस बात पर बल देता है कि शैक्षिक सविधायें व्यक्तियों की माँग के अनुपात में ही दी जानी चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि शैक्षिक विस्तार की कोई सीमा ही न हो। सामाजिक माँग मॉडल ही केवल ऐसा विचार नहीं जो शैक्षिक नियोजन को निर्देशित करें स्वयं इसके पैरामीटर को निर्धारित करे यदि शिक्षा के लिए सामाजिक माँग को ही पूरा महत्तव दिया जाता है तो यह बेरोजगारी को तथा शिक्षित अन्ध बेरोजगारी को जन्म देगी जो अन्त में सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता को धक्का पहुँचा सकती है। अतः सभी मॉडलो को संतुलित ध्यान देने की जरूरत है।

प्राप्ति दर या विनियोग उपागम (मॉडल)
(The Rate of return apporach) इसको शैक्षिक नियोजन के लागत लाभ (Cost benefit) या लागत प्रभावशीलता (cost effectiveness) मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह मॉडल इस बात पर बल देता है कि

शिक्षा में निवेश-व्यय इससे प्राप्त होने वाले लाभ या प्राप्ति पर आधारित होना चाहिए। इस उपागम में यह धारणा निहित है कि शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय निवेश-व्यय के रूप में लिया जाना चाहिए। जिसकी पुष्टी शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा अधिक उत्पादन तथा अधिक आय के रूप में द्वारा की जा सकती है। शिक्षा को कभी भी अपने में साध्य नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर इसे केवल निवेश व्यय के रूप में भी नहीं लिया जा सकता। इसको आर्थिक विकास के साथ जोड़ना आवश्यक है। निवेश व्यय के रूप में शिक्षा का अर्थ बातों से है—

(1) प्रशिक्षण संस्थानो द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी की उत्पादन क्षमता विकसित होनी चाहिए।

(२) शिक्षित व्यक्ति की आय का स्तर अशिक्षित व्यक्ति की आय से ऊँचा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि शिक्षा पर प्राप्ति सकारात्मक है।

सैद्धान्तिक रूप से शिक्षा में निवेश व्यय व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनो के स्तर पर उस समय तक सकारात्मक होगा जब तक शिक्षित बेरोजगारी नहीं है। सकारात्मक निवेश व्यय शिक्षा तथा राष्ट्र की मानव शक्ति माँग के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पर निर्भर करता है। शिक्षा के लिए यह आशा की जाती है कि वह व्यक्ति तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए लाभकारी होगी।

Scanned by CamScanner

Kinds of Educational Planning

(शैक्षिक नियोजन के प्रकार)

उपयुक्त सन्दर्भ पर निर्भर करते हुए निर्णय लेते समय नियोजन के कई प्रकार हैं। उनमें से कुछ आगे दिये जा रहे हैं :

① **सामरिक नियोजन (Strategic Planning)** →: इसे दीर्घ कालीन नियोजन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्पूर्ण व्यवस्था को फोकस करता है। यह संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है तथा विभिन्न स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों को भी निर्दिष्ट करता है। दीर्घकालीन नियोजन दस से बीस वर्ष तक की अवधि का होता है तथा बृहद परिपेक्ष्य पर आधारित होता है।

② **अल्पकालीन नियोजन (Short-term Planning)** →: अल्पकालीन नियोजन का परिणाम एक ऐसी योजना होता है जो 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। यह दबावयुक्त व तात्कालिक समस्याओं के समाधान पर फोकस करती है। विशिष्ट एवं लघु उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन नियोजन अधिक उपयुक्त है।

③ **प्रबन्ध नियोजन (Management Planning)** →: इसका तात्पर्य उन निर्णयों से है जो तैयार योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु लिये जाते हैं। इसका सम्बन्ध लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्रभावशीलता एवं दक्ष प्राप्ति से है। यह नियोजन प्रक्रिया का एक अंग है जो मूल निर्णयों को लेने के बाद क्रियान्वित किया जाता है इसका प्रयोग दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों ही प्रकार की योजनाओं में किया जाता है।

(4) **आधार नियोजन (Grass-Root Planning)** →: शैक्षिक नियोजन अनेक स्तरों पर किया जा सकता है अर्थात् राष्ट्रीय स्तर, राजकीय स्तर,

Scanned by CamScanner

जिला स्तर, ब्लाक स्तर या संस्थागत स्तर। राष्ट्रीय स्तर का नियोजन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत व्यापक है तथा उन सभी कारको को ध्यान में रखता है जो राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रो के समन्वित एवं सन्तुलित विकास को सुनिश्चित करते है। राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत विशिष्ट एवं विस्तृत योजनाऐं भी राजकीय, जिला, ब्लाक या संस्थागत स्तर पर तैयार की जा सकती है।

(5) क्षेत्र नियोजन (Area Planning) :- क्षेत्र नियोजन जिला स्तर पर नियोजन के समान है, यह भी आधार स्तर नियोजन का ही एक रूप है। जिला स्तर के नियोजन एवं क्षेत्र नियोजन के बीच अन्तर केवल क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र का है। जिला स्तर के नियोजन में ध्यान का केन्द्र जिला होता है जोकि निश्चित होता है, क्षेत्र नियोजन के मामले में यह कोई विशिष्ट क्षेत्र हो सकता है। जिस पर विकास के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र नियोजन में योजना को क्रियान्वित करने के लिए अलग से बजट रहता है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए स्थानीय सत्ता को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।

⑥ संस्थागत नियोजन (Institutional Planning) :-

आधार-स्तर नियोजन में से एक संस्थागत नियोजन है। यह सबसे निम्न-स्तर का होता है जिस पर नियोजन किया जाना आवश्यक है। इसके द्वारा उन संसाधनो के सर्वोत्तम और अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित किया जाता है जो एक संस्था के पास होते है या हो सकते है। संस्था ही अपनी उन आवश्यकताओं और समस्याओं को अच्छी तरह जान सकती है जिनको पूरा किया जाना है एवं जिनका समाधान किया जाना है। इसलिए संस्था ही अपने कल्याण एवं विकास के

Scanned by CamScanner

लिए सर्वोत्तम योजना बना सकती है।
शैक्षिक नियोजन के उत्तरदायित्व को नियोजित तथा व्यवस्थित विकास एवं उन्नति के माध्यम से वैयक्तिक संस्थाओं के द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक संस्था की अपनी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनायें होनी चाहिए। अतः "संस्थागत नियोजन" से तात्पर्य उन योजनाओं से है जो व्यक्तिगत शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ की जाती है निर्मित की जाती है एवं क्रियान्वित की जाती है।

संस्थागत नियोजन का महत्व →:
(Importance of Institutional Planning) →

संस्थागत नियोजन से कई उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है:—

(a) संप्रभुता को निश्चित करता है (Ensure Autonomy) →:

शैक्षिक संस्थाऐं प्रायः अपनी संप्रभुता (स्वायत्ता) के लिए लड़ती है। संप्रभुता का तात्पर्य अपनी उन्नति एवं विकास की योजना बनाने तथा उसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने की स्वतन्त्रता से है।

(b) स्थिरता प्रदान करता है (Gives Stability) →:

एक शैक्षिक संस्थान में स्थिरता का होना आवश्यक है। नियोजित एवं व्यवस्थित रूप में कार्य करने से नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रक्रियाओं की निरन्तरता तथा उनमें सुधार सुनिश्चित है। इस प्रकार संस्थागत नियोजन संस्था को स्थिरता तथा शक्ति प्रदान करता है।

(c) समस्याओं के समाधान में सहायक है (Helps in Solving Problems) →:

शैक्षिक प्रशासन को कुछ कारक प्रभावित करते है जिनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण स्टाफ और

विद्यार्थियों की विभिन्न व्यक्तित्व तथा वातावरण की परिवर्तनशील परिस्थितियाँ हैं। प्रत्येक कार्य आशानुसार आगे नहीं बढ़ता और वह अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। इनमें से अधिक समस्याएं संस्था में विशिष्ट होती हैं तथा कुछ सभी में सामान्य होती हैं। संस्थागत नियोजन इन समस्याओं को ध्यान में रखता है तथा उनके समाधान में सहयोग देता है। इस प्रकार संस्था की कार्य-प्रणाली को सरल बनाता है।

(d) सुधार लाता है (Brings about Improvement) →:

शिक्षा एक गतिमान प्रक्रिया है। इसकी आवश्यकताएं एवं समस्याएं परिस्थितियों के अनुसार बदल रही हैं। अच्छे शैक्षिक कार्यकर्ता अपनी वर्तमान उपलब्धि से कभी भी सन्तुष्ट नहीं होते, अपितु अच्छे ढंग से कार्य में संलग्न रहते हैं। संस्थागत नियोजन संस्था के प्रतिदिन के कार्य में वांछित सुधार का ध्यान रखता है। इस प्रकार सिखने-सिखाने की प्रक्रिया प्रक्रिया, पाठ्य सम्बन्धी तथा पाठ्येत्तर कार्यकलाप सभी में सुधार किया जाता है।

(e) भावी उन्नति को सुरक्षित करता है (Secures Future Progress) →:

जीवन तथा शिक्षा दोनों ही गतिशील हैं। शैक्षिक प्रशासन का दृष्टिकोण व्यावहारिक एवं विकासात्मक होना चाहिए। अच्छे प्रशासक का उद्देश्य निरन्तर भावी उन्नति करना होता है। संस्थागत नियोजन चाहे वह दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन भविष्य की ओर देखता है। यह स्व-सहायता तथा स्व-प्रयास द्वारा निरन्तर भावी तरक्की की

Scanned by CamScanner